अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 संख्या 19 श्री विजय पुरम, सोमवार, 19 जनवरी 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अण्डमान सागर के नॉर्थ बे में भारत की पहली ओपन–सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना का शुभारंभ किया

केंद्रीय मंत्री ने इसे भारत के विशाल समुद्री संसाधनों के माध्यम से ब्लू इकोनॉमी को साकार करने की दिशा में पहले बड़े कदमों में से एक बताया है, जिसकी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कल्पना की गई है और इस पर लगातार ज़ोर दिया गया है

श्री विजय पुरम, 18 जनवरी

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज अण्डमान सागर से भारत की पहली ओपन–सी (खुले समुद्र में) समुद्री मत्स्य पालन परियोजना का शुभारंभ किया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसे भारत के विशाल समुद्री संसाधनों के माध्यम से ब्लू इकोनॉमी को साकार करने की दिशा में पहले बड़े कदमों में से एक बताया, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी और लगातार इस पर ज़ोर दिया गया है। इस परियोजना का शुभारंभ अण्डमान सागर के खुले जल क्षेत्र के फील्ड दौरे के दौरान, नॉर्थ बे, श्री विजय पुरम में साइट पर ही किया गया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह पहल भारत के समुद्रों की आर्थिक क्षमता के द्वार खोलने के लिए उठाए गए शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत के समुद्रों में भी, हिमालय और मुख्यभूमि के संसाधनों की तरह ही, विशाल और विविध आर्थिक संभावनाएं मौजूद हैं, जिन पर दशकों तक उचित ध्यान नहीं दिया गया था।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद लगभग सत्तर वर्षों तक, भारत के समुद्री संसाधन काफी हद तक अनछुए रहे। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि 2014 के बाद से, राष्ट्रीय सोच में एक बुनियादी बदलाव आया है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि भारत का समुद्री क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए समान रूप से संपदा और अवसर रखता है। उन्होंने आगे भारत के समुद्रों की विशिष्ट और विविधतापूर्ण प्रकृति पर प्रकाश डाला और कहा कि पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी तटों में से प्रत्येक की अपनी अलग विशेषताएं हैं और वे देश के विकास में अद्वितीय योगदान देने की क्षमता रखते हैं।

इस परियोजना को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसकी तकनीकी शाखा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के बीच सहयोग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह पायलट पहल प्राकृतिक समुद्री परिस्थितियों में समुद्री फिनफिश और समुद्री शैवाल की ओपन–सी खेती पर केंद्रित है, जो वैज्ञानिक नवाचार को आजीविका सृजन के साथ जोड़ती है।

फील्ड विजिट के दौरान, आजीविका को बढ़ावा देने वाले दो प्रमुख कार्य शुरू किए गए। समुद्री वनस्पति के तहत, डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय मछुआरा समुदायों को समुद्री शैवाल के बीज सौंपे गए ताकि खुले समुद्र के गहरे पानी में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा सके। समुद्री जीव वाले हिस्सों में पिंजरा–आधारित पालन के लिए फिनफिश के चारे प्रदान किए गए, जिसे एनआईओटी द्वारा विकसित उन ओपन–सी केज का सपोर्ट प्राप्त है जिन्हें प्राकृतिक समुद्री वातावरण में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हालांकि वर्तमान परियोजनाएं सरकार के नेतृत्व वाले सहयोग के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, लेकिन इनसे प्राप्त अनुभव और फिजिबिलिटी असेसमेंट भविष्य में सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से ऐसी पहलों के विस्तार को सक्षम बना सकते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि यह दृष्टिकोण तकनीक की तैनाती को तेज करने, आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और भारत के ब्लू इकोनॉमी इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा।

कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें डॉ. रविचंद्रन, सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, श्रीमती ज्योति कुमारी, सचिव (मत्स्य), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, डॉ. जी. धरनी, समूह निदेशक, एमबीटी–एनआईओटी,

डॉ. दिलीप कुमार झा, परियोजना निदेशक, एनआईओटी–एकोस्टी, श्रीमती जगताप कल्याणी राजेंद्र, निदेशक (मत्स्य), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, श्री देबदास पैक, प्रबंधक, इस्ट्रैक–इसरो, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख, आईएमडी, सहित विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

बाद में, अपनी अण्डमान द्वीप यात्रा के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने वंडूर के पास स्थित महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान (एमजीएमएनपी) का भी दौरा किया। यह 1983 में स्थापित देश के अपनी तरह के पहले समुद्री उद्यानों में से एक है। 15 द्वीपों में फैले और वंडूर जेटी के माध्यम से सुलभ, यह पार्क जॉली बॉय और रेड स्किन जैसे अपने संरक्षित द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। डॉ. सिंह ने पार्क के समृद्ध और आत्मनिर्भर समुद्री इकोसिस्टम का अवलोकन किया, जिसमें जीवंत मूंगा चट्टानें, मैंग्रोव और कछुए व मछलियों की विभिन्न प्रजातियों जैसे विविध समुद्री जीवन शामिल हैं।

नॉर्थ बे से इस परियोजना का शुभारंभ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सीधे कार्यक्षेत्र तक ले जाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि तटीय और द्वीप समुदाय भारत के समुद्र–आधारित आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनें। (स्रोत : प.सू.का./स्टाफ संवाददाता)

लखपति दीदी बनीं श्रीमती एम. सुधा देवी, महिला उद्यमिता और सतत आजीविका की मिसाल

श्री विजय पुरम, 18 जनवरी

निकोबार ज़िले के सामुदायिक विकास खंड, कैंपबेल बे की श्रीमती एम. सुधा देवी महिला नेतृत्व वाली उद्यमिता और सतत आजीविका सृजन की एक प्रेरक मिसाल बनकर उभरी हैं। उन्होंने "लखपति दीदी" के रूप में पहचान हासिल की है।

नीला स्वयं सहायता समूह की स्थापना अक्टूबर, 2017 में हुई थी, जिससे 40 वर्षीय श्रीमती एम. सुधा देवी जुड़ीं। वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते हुए, उन्होंने अपने स्वयं सहायता समूह की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं तथा छोटे खाद्य प्रसंस्करण उपकरणों की खरीद के लिए सहयोग प्राप्त किया।

ग्रामीण विकास विभाग के सतत सहयोग से, नीला स्वयं सहायता समूह को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएफएमई) योजना के तहत 40,000 रुपये की सीड कैपिटल सहायता प्राप्त हुई। इस वित्तीय सहायता से ग्राइंडर की खरीद संभव हुई, जिससे उद्यम की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मशीनरी की स्थापना के बाद दैनिक उत्पादन क्षमता 10 किलोग्राम प्रति लीटर से बढ़कर 12 किलोग्राम प्रति लीटर हो गई, जिससे दैनिक लाभ 450 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो गया। सीड कैपिटल

शेष पृष्ठ 4 पर

पुलिस स्थापना सप्ताह के तहत 'नमन' सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया

श्री विजय पुरम, 18 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार पुलिस द्वारा 74वें पुलिस स्थापना सप्ताह समारोहों के अंतर्गत कल मरीना पार्क, श्री विजय पुरम में "नमन" शीर्षक से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों, पुलिसकर्मियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, श्री हरगोबिंदर सिंह धालीवाल (आईपीएस) रहे। इस अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन और अण्डमान तथा निकोबार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों, पुलिसकर्मियों तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों की उपस्थिति रही, जो पुलिस–जनसंपर्क की मजबूत भावना और बलिदानों के प्रति सामूहिक सम्मान को दर्शाती है।

सांस्कृतिक संध्या में देशभक्ति गीत, ब्रास बैंड की प्रस्तुतियां और भारत की "एकता में विविधता" को दर्शाने वाले सांस्कृतिक नृत्य शामिल

शेष पृष्ठ 4 पर

हटबे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6.979 किलोग्राम मेथामफेटामिन बरामद

श्री विजय पुरम, 18 जनवरी

नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थों (एनडीपीएस) के विरुद्ध चल रही मुहिम के तहत पुलिस स्टेशन हटबे, लिटिल अण्डमान की टीम ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए 6.979 किलोग्राम क्रिस्टलीय मेथामफेटामिन बरामद किया है। 16 जनवरी, 2026 को पुलिस स्टेशन हटबे के थानाध्यक्ष निरीक्षक प्रीतम बिहारी को डुगोंग क्रीक, पगला मुंडी के समीप जंगल क्षेत्र में संदिग्ध हरे रंग के पैकेट छिपाए जाने संबंधी विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई, जिनमें मादक पदार्थ होने की आशंका थी। सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई शुरू की गई।

थानाध्यक्ष, पुलिस स्टेशन हटबे के नेतृत्व में एक पुलिस छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें दो स्थानीय पीआरआई प्रतिनिधि भी स्वतंत्र गवाह के रूप में स्वेच्छा से शामिल हुए। ड्रग डिटेक्शन किट एवं इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से सुसज्जित पुलिस दल निजी डिंगी के माध्यम से डुगोंग क्रीक पहुंचा और जंगल क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी के दौरान एक बड़े पेड़ की जड़ों के पास रेत में आंशिक रूप से दबे तथा सूखी पत्तियों से ढके कुल सात संदिग्ध पैकेट बरामद किए गए। ड्रग डिटेक्शन किट से परीक्षण करने पर इनमें मेथामफेटामिन पाया गया। बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 6.979 किलोग्राम था। सभी कानूनी एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का सख्ती से पालन करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में मौके पर ही मादक पदार्थ को सील किया गया। इस संबंध में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज़ कर आगे की जांच जारी है, ताकि इसमें संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।

दक्षिण अण्डमान के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा जारी विज्ञप्ति में आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी अपराध अथवा अवैध गतिविधियों से संबंधित जानकारी पुलिस को 112, 03192–232100 एवं 03192–236641 नंबरों पर साझा करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ निर्णायक कदम: एचपीवी टीकाकरण और डीएनए जांच पर सरकार का ज़ोर

नई दिल्ली, 18 जनवरी।

मानव पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के खिलाफ टीकाकरण और डीएनए आधारित स्क्रीनिंग तक पहुंच को मजबूत करना भारत में सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के लिए बेहद जरूरी है। यह बात स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने शनिवार को कही। ये विशेषज्ञ एम्स द्वारा आयोजित भारत के पहले राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे, जिसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के एजेंडे को तेज करना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त सचिव और प्रबंध निदेशक अराधना पटनायक ने सर्वाइकल कैंसर को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "भारत के लिए सर्वाइकल कैंसर का उन्मूलन एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है और हम रोकथाम, स्क्रीनिंग और उपचार– तीनों स्तरों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"

पटनायक ने आगे कहा, "हमारा फोकस एचपीवी टीकाकरण के तेजी से विस्तार और सभी स्तरों पर स्क्रीनिंग को मजबूत करने पर है, खासकर एचपीवी डीएनए टेस्टिंग जैसी उच्च प्रदर्शन वाली विधियों के जरिए, ताकि हर महिला को समय पर जांच और इलाज मिल सके। मजबूत प्रणालियों, स्पष्ट संचालन प्रोटोकॉल और राज्यों व अन्य हितधारकों के साथ सतत साझेदारी के जरिए हम सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को वास्तविकता बना सकते हैं और देशभर की लाखों महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं।" नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) प्रो. डॉ. वीके. पॉल ने कहा, "भारत के पास सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने का ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन इसके लिए तेजी, व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन और पूरे सिस्टम का समन्वय जरूरी है।" उन्होंने साक्ष्य–आधारित कार्यान्वयन मॉडल की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "हमें ऐसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे, जो यह दिखाएं कि एचपीवी डीएनए आधारित स्क्रीनिंग और सेल्फ–सैंपलिंग को बड़े पैमाने पर, खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, कैसे लागू किया जा सकता है। इससे भारत को एक राष्ट्रीय मॉडल विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे हर महिला को समय पर स्क्रीनिंग, सटीक जांच और प्रभावी फॉलो–अप का लाभ मिल सके।" एम्स के डॉ. बीआर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और ऑनको–एनेस्थीसिया एवं पैलिएटिव मेडिसिन विभागों द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का फोकस तीन प्रमुख स्तंभों पर रहा। इनमें एचपीवी टीकाकरण के विस्तार से लेकर उच्च प्रदर्शन वाली एचपीवी डीएनए टेस्टिंग के जरिए स्क्रीनिंग को मजबूत करना, सेल्फ–सैंपलिंग विधियों को बढ़ावा देना और प्रभावी कैंसर उपचार के साथ पूरी प्रक्रिया को जोड़ना शामिल था। सम्मेलन में एकरूप राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करने, हब–एंड–स्पोक केयर मॉडल लागू करने और इलाज व फॉलो–अप की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी चर्चा हुई, ताकि देशभर में समान और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल सुनिश्चित की जा सके। एम्स के डॉ. बीआर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अभिषेक शंकर ने कहा, "सर्वाइकल कैंसर से अब अलग–थलग तरीके से नहीं निपटा जा सकता। सरकार, चिकित्सकों, नवोन्मेषकों और मरीज प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाना रोकथाम, शुरुआती पहचान और प्रभावी इलाज को तेज करने के लिए जरूरी गति और जवाबदेही पैदा करता है।" उन्होंने कहा, "इस पहल के जरिए हमारा लक्ष्य स्पष्ट और व्यावहारिक सिफारिशें तय करना है, जो भारत के सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन रोडमैप को दिशा देंगी।" इस शिखर सम्मेलन में देशभर के एम्स संस्थानों, राज्य स्वास्थ्य विभागों, कैंसर संस्थानों, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, आईसीएमआर, सिविल सोसायटी संगठनों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन एक राष्ट्रीय 'कॉल टू एक्शन' के साथ हुआ, जिसमें भारत में सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को तेज करने के लिए प्राथमिक कदमों की रूपरेखा तय की गई।

पुलिस स्थापना सप्ताह के तहत 'नमन' ——————————पृष्ठ 1 का शेष

रहे। इसके साथ ही नशा उन्मूलन, मद्यपान और साइबर अपराध पर आधारित चेतना नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसने सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक कल्याण के प्रति पुलिस बल की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

पुलिस अधीक्षक (सशस्त्र पुलिस इकाई) से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्यक्रम 74वें पुलिस स्थापना सप्ताह समारोहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जिसने त्याग, सेवा और एकता के मूल्यों को सुदृढ़ करने के साथ–साथ परिचालन दायित्वों से इतर पुलिसकर्मियों की प्रतिभा और समर्पण को भी प्रदर्शित किया।

लखपति दीदी बनीं श्रीमती एम. सुधा देवी, ——————————पृष्ठ 1 का शेष

सहायता का उपयोग उद्यम की निरंतर कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

निरंतर उत्पादन, बेहतर दक्षता और बाज़ार तक पहुंच के माध्यम से, श्रीमती एम. सुधा देवी ने वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक अर्जित कर "लखपति दीदी" का दर्जा प्राप्त किया। नीला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद स्थानीय बाज़ारों में बेचे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान समूह का कुल वित्तीय कारोबार 1,40,000 रुपये दर्ज़ किया गया।

लखपति दीदी श्रीमती एम. सुधा देवी की यह सफलता कहानी महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सशक्त बनाने, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण एवं द्वीपीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणास्रोत है।

(स्रोत :एएनआईआरएलएम यूटी)

विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर : एनसीसी कैडेटों ने बाराटांग स्थित चूना पत्थर की गुफाओं और वंडूर तट का दौरा किया

श्री विजय पुरम, 18 जनवरी

चल रहे विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर (एसएनआईसी) के अंतर्गत, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटों ने मध्य अण्डमान के बाराटांग स्थित प्रसिद्ध चूना पत्थर की गुफाओं का शैक्षिक और साहसिक दौरा किया। घने मैंग्रोव जलमार्गों और वन मार्गों से होते हुए गुफाओं तक पहुँचकर कैडेटों ने क्षेत्र की जैव विविधता का अनुभव किया और भूवैज्ञानिक चमत्कार को देखा। यात्रा कार्यक्रम में दक्षिण अण्डमान के वंडूर तट का भ्रमण भी शामिल था। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह दौरा एनसीसी सेना इकाई के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल के.वाई. सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिससे पूरे अभियान के दौरान अनुशासन, सुरक्षा और सार्थक शिक्षा सुनिश्चित हुई।

'डीब्राइट' द्वारा नियमित एनएसएस शिविर आयोजित

श्री विजय पुरम, 18 जनवरी

डॉ. बी. आर. आंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट), पहाड़गांव, श्री विजय पुरम की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई–2 द्वारा 17 जनवरी, 2026 को बिड़नाबाद ग्राम, प्रोथरापुर तहसील, दक्षिण अण्डमान में नियमित एनएसएस शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एनएसएस की नियमित गतिविधियों तथा ग्रामीण इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से अनुभवात्मक अधिगम प्रदान करना था।

इस शिविर में बी.टेक प्रथम वर्ष के कुल 34 एनएसएस स्वयंसेवकों ने डॉ. ई. मुथु कुमारन, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी (इकाई–2) के मार्गदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में श्री विवेकानंद डी. नाइक, सहायक निदेशक, दूरसंचार विभाग, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

ग्राम दत्तक ग्रहण पहल के अंतर्गत बिड़नाबाद ग्राम को वर्ष 2025–2027 की अवधि के लिए एनएसएस इकाई–2 द्वारा गोद लिया गया है, ताकि ग्रामीण विकास, जन–जागरूकता एवं छात्र इंटर्नशिप से संबंधित नियमित एवं विशेष शिविरों का आयोजन किया जा सके। ग्रामीण इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने, ग्रामीण समस्याओं को समझने तथा सेवा–आधारित अधिगम के माध्यम से योगदान देने का अवसर मिला।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार ग्राम सामुदायिक भवन में सामुदायिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री परमशिवम, प्रधान, बिड़नाबाद ग्राम एवं श्रीमती पिचायम्मल, पंचायत समिति सदस्य ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इंटर्नशिप एवं जनसंपर्क गतिविधियों के अंतर्गत संचार साथी ऐप पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस स्वयंसेवकों एवं संचार मित्र स्वयंसेवकों द्वारा दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया।

इस सत्र में विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई, जिनमें दूरसंचार धोखाधड़ी की रोकथाम, चक्षु के माध्यम से स्पैम एवं संदिग्ध संचार की रिपोर्टिंग, किसी व्यक्ति के नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों का सत्यापन तथा खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक एवं ट्रेस करना आदि शामिल हैं।

इस ग्रामीण इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों ने स्थानीय स्तर के प्रशासन, ग्रामीण डिजिटल चुनौतियों एवं सामुदायिक समस्या–समाधान की प्रक्रियाओं की बहुमूल्य समझ प्राप्त की, वहीं ग्रामीणों को दूरसंचार सुरक्षा तथा सरकारी डिजिटल पहलों के संबंध में बेहतर जागरूकता प्राप्त हुई।

यह कार्यक्रम ग्रामीणों, स्वयंसेवकों, संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिससे "नॉट मी, बट यू" के आदर्श वाक्य के अंतर्गत सामुदायिक सेवा एवं अनुभवात्मक अधिगम के एनएसएस उद्देश्यों को सुदृढ़ किया गया।

कयाकिंग एवं कैनोइंग चैंपियनशिप 24 जनवरी से

श्री विजय पुरम, 18 जनवरी

अण्डमान तथा निकोबार कयाकिंग एवं कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा 24 जनवरी, 2026 से विभिन्न चैंपियनशिप आयोजित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सीनियर, जूनियर और सब–जूनियर वर्गों के लिए ओपन स्टेट कयाकिंग एवं कैनोइंग चैंपियनशिप, एएसएमआईटीए कयाकिंग एवं कैनोइंग लीग के साथ, निम्नलिखित विवरण के अनुसार श्री विजय पुरम में आयोजित की जाएगी।

1.	ओपन स्टेट सीनियर चैंपियनशिप–सह–चयन ट्रायल 24 जनवरी, 2026 को आयोजित किया जाएगा।	सभी के लिए खुला	प्रवेश की अंतिम तिथि 23 जनवरी, 2026
2.	एएसएमआईटीए लीग 31 जनवरी, 2026	केवल महिला प्रतिभागियों के लिए खुला	प्रवेश की अंतिम तिथि 29 जनवरी, 2026
3.	जूनियर एवं सब–जूनियर ओपन स्टेट चैंपियनशिप–सह–चयन ट्रायल 1 फरवरी, 2026 को होगी	जूनियर (जन्म तिथि 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2012 तक) सब–जूनियर (जन्म तिथि 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसंबर, 2014 तक)	प्रवेश की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2026

प्राप्त विज्ञप्ति में एसोसिएशन ने सभी पैडलरों को सलाह दी है कि वे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां पंजीकृत करें। गूगल फॉर्म का लिंक अण्डमान तथा निकोबार कयाकिंग एवं कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। संपर्क नंबर 9679525733 एवं 7695056200 हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय समय के दौरान राज्य ओलंपिक संघ कार्यालय, नेताजी स्टेडियम, श्री विजय पुरम से संपर्क कर सकते हैं।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

SBI नीलामी सूचना

हमारे ब्रांचों से कार/स्पीड बोट के लिए लोन लेने वाले कुछ लोगों ने निर्धारित समय पर लोन चुकाने में चूक की है। उन्होंने नोटिस का ठीक से जवाब नहीं दिया है या नोटिस वापस आ गए हैं। इन परिस्थितियों में, यह निर्णय लिया गया है कि यदि 22/01/2026 को शाम 4.00 बजे से पहले लोन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी 23/01/2026 को दोपहर 3.00 बजे एसबीआई, मुख्य शाखा परिसर, श्री विजय पुरम में बिना किसी पूर्व सूचना के की जाएगी।

इस संबंध में होने वाले सभी खर्च उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे। बैंक किसी भी समय नीलामी को स्थगित/रद्द करने और बीच में ही नीलामी रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सफल बोलीदाताओं को पूरी राशि का भुगतान करके उक्त वाहन का कब्जा प्राप्त करना होगा या बोली राशि का कम से कम 25 प्रतिशत मौके पर जमा करना होगा और शेष राशि 7 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि 7 दिनों के भीतर शेष भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक प्रारंभिक जमा राशि जब्त कर सकता है। वाहन 'जैसे हैं वैसे ही' आधार पर बेचे जाएंगे।

वाहन एसबीआई की मुख्य शाखा परिसर में सभी कार्य दिवसों में सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक प्रदर्शन के लिए उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए फोन संख्या 8334850949/9434263949 पर संपर्क करें। नीलामी के लिए वाहनों का विवरण इस प्रकार है :–

क्रमांक	वाहन निर्माता	प्रकार	निर्माण वर्ष	चेसिस नं./परमिट नं./Regn.No.	मूल्यांकित कीमत
1	अशोका लेलैंड लिमिटेड	मालवाहक वाहन (एचजीवी) जीए 1920–4750 एमएमडब्ल्यूबी	2020	MB1A9CHD9LRDE3383 AN 01 Q 3653	रु. 10,50,000.00
2	फोर्ड	ईको स्पोर्ट 1.5 डी (व्यक्तिगत)	2016	MAJAXXMRKAGS75131/ AN 01 L 7407	रु. 2,20,000.00
3	टाटा	नेक्सॉन XZ+S RTN BS-2023 VI टॉप मॉडल (व्यक्तिगत)	2023	MAT627021PLE56188/ AN 01 R 9914	रु. 6,90,000.00
4	जेटस्की	जेटस्की टाइटेनियम सीडीओ जीटीएस 18 सीई एफआरपी नाव	2018	MN000637 AN/DC(SA) 579/2019	रु. 2,55,000.00
5	डैटसन	गो प्लस टी (ओ) बीएस IV (7 सीटर) (व्यावसायिक)	2018	MDHJBAAD0JA706562 AN 01 N 8743	1,60,000.00

नोट : नीलामी के लिए बोली में रु. 10,000 की वृद्धि होनी चाहिए।

ह./–
अधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

दिनांक : 16.01.2026
स्थान : श्री विजय पुरम

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, बृंदाबन की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारों से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2025–26/188
कार्य का नाम : बृंदाबन, ग्राम पंचायत के अंर्तगत वार्ड न. 04 में मुख्य सड़क से चर्च कॉलोनी तक 300 मीटर की लंबाई वाली 01 पुलिया सहित ग्राम सड़क और दोनों ओर की नालियों की मरम्मत और रखरखाव।
अनुमानित लागत : रु. 45,25,508/–, धरोहर राशि : रु. 90,510/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 22/01/2026 के सायं 3.00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_21458_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, शोल बे की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2025–26/187
कार्य का नाम : शोल बे, ग्राम पंचायत के अंर्तगत शोल बे 08 में मुख्य सड़क से संजय पान की दुकान तक जाने वाली ड्रेन सहित सी सी रोड की नवीनीकरण।
अनुमानित लागत : रु. 7,45,546/–, धरोहर राशि : रु. 14,911/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (04) चार माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 22/01/2026 के सायं 3.00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_21509_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

उप वन संरक्षक का कार्यालय, मिल प्रभाग चाथम

ई–टेंडर आमंत्रण सूचना

उप वन संरक्षक, मिल डिवीजन, चाथम, पर्यावरण एवं वन विभाग, श्री विजय पुरम द्वारा पात्र एवं वास्तविक ठेकेदारों/फर्मों, जिनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज न हो, से निम्नलिखित कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है :

एनआईटी संख्या	No.76/Genl/MD/2025-26/Furniture Showroom at GSM/629, दिनांक 13.01.2026
कार्य का नाम	राजस्व साझेदारी के आधार पर सरकारी आरा मिल, चाथम में लकड़ी के फर्नीचर एवं अन्य लकड़ी उत्पादों के जमा कार्यों का आउटसोर्सिंग।
बयाना राशि (Earnest Money)	रु. 66,724/–
पूरा होने की अवधि	12 (माह)
बिड जमा करने की अंतिम तिथि	28.01.2026 (सुबह 11.00 बजे)
बिड खोलने की तिथि	29.01.2026 (सुबह 11.00 बजे)
टेंडर आईडी 2026_DCFMD_21473_1	

टेंडर का विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।
कार्य का दायरा : ठेकेदार/फर्म को GSM चाथम परिसर में आम जनता के लिए लकड़ी से बने सामान, फर्नीचर एवं अन्य संबंधित वस्तुओं का निर्माण करना होगा। यह कार्य GSM चाथम के साथ राजस्व साझेदारी के आधार पर किया जाएगा।
पात्रता मानदंड : केवल वे लघु उद्योग (SSI) इकाइयाँ, जो अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन में पंजीकृत हों, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगी।
चयन की विधि : न्यूनतम आधार दर 15 प्रतिशत के अधीन, सरकार को सर्वाधिक राजस्व हिस्सेदारी प्रदान करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।
एक पूर्व–बिड बैठक चैमबर ऑफ द चेयरमैन, पर्चेज कमिटी, मिल डिवीजन, चाथम में आयोजित की जाएगी, दिनांक 20.01.2026 को सुबह 11.00 बजे पर, ताकि टेंडर से संबंधित विवरण स्पष्ट किए जा सकें और बोली लगाने वालों के प्रश्नों का समाधान किया जा सके। सभी इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे समय पर उपस्थित हों ताकि आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से समझा जा सके।

वन उप संरक्षक, मिल प्रभाग, चाथम

सवाई माधोपुर में देश का पहला अमरूद महोत्सव शुरू

सवाई माधोपुर, 18 जनवरी। सवाई माधोपुर में रविवार से देश का पहला अमरूद महोत्सव शुरू हो गया। जिले के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह महोत्सव दशहरा मैदान में मंगलवार तक चलेगा। इस अनूठे आयोजन में देशभर से 10 हजार से अधिक किसान भाग ले रहे हैं।

महोत्सव में अमरूद की 30 से अधिक किस्मों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही अमरूद से बने प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स, कृषि यंत्रीकरण एवं ऑटोमेशन, उद्यानिकी तकनीक, कृषि आदान और समन्वित खेती आधारित पशुधन गतिविधियों के लाइव डेमो सहित करीब 200 तरह की स्टॉल्स लगाई गई हैं।

महोत्सव का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किया। दोनों नेताओं ने किसानों से संवाद किया और विभिन्न स्टॉल्स पर जाकर अलग–अलग किस्म के अमरूद चखे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अमरूद के अनेक आयुर्वेदिक फायदे हैं और यह कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में सहायक है। उन्होंने घोषणा की कि सवाई माधोपुर में 150 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और भजनलाल सरकार एग्रोटेक इंडस्ट्री के जरिए किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रही है।

महोत्सव के दौरान लोक कलाकारों ने पद दंगल और लोकगीतों की प्रस्तुतियां दीं। कृषि मंत्री के लिए गाए गए लोकगीत "बाबो लायो नई स्कीम" और "बाबो लायो अमरूद" पर लोग झूमते नजर आए। मंच पर पहुंचते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा का पारंपरिक लोकगीतों से स्वागत किया गया।

रणथंभौर टाइगर सफारी पर आए विदेशी पर्यटक भी अमरूद महोत्सव में शामिल हुए। वे लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर स्थानीय कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए, जिससे महोत्सव की रौनक और बढ़ गई।

महोत्सव में भरतपुर से आए किसान विष्णु मित्तल ने बताया कि देश के अलग–अलग हिस्सों से किसान यहां पहुंचे हैं, लेकिन उनके लिए ठहरने और खाने–पीने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अमरूद महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर किसानों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है।

केंद्रीय बजट 2026–27 दस्तावेजों की छपाई का काम नॉर्थ ब्लॉक की प्रेस में ही होगा

नई दिल्ली, 18 जनवरी। वित्त मंत्रालय का मुख्यालय नई सचिवालय इमारत 'कर्तव्य भवन' में स्थानांतरित हो जाने के बावजूद बजट संबंधी बेहद गोपनीय दस्तावेजों की छपाई का काम वित्त मंत्रालय के पुराने मुख्यालय नॉर्थ ब्लॉक में स्थित सरकारी प्रेस में ही होगा।

सूत्रों ने जानकारी में बताया कि केंद्रीय बजट 2026–27 और उससे संबंधित दस्तावेजों की छपाई नॉर्थ ब्लॉक में स्थित सरकारी प्रेस में ही होगी। इसकी वजह यह है कि कर्तव्य भवन में अभी तक प्रिंटिंग प्रेस मौजूद नहीं है। वित्त मंत्री और उनकी अधिकांश टीम सितंबर, 2025 में ही नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय से निकलकर नवनिर्मित कर्तव्य भवन में स्थानांतरित हो गई थी।

इससे पहले बजट की छपाई का काम राष्ट्रपति भवन में होता था, जिसे 1950 में मिंटो रोड स्थित प्रेस में स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद वर्ष 1980 से ये काम नॉर्थ ब्लॉक की प्रेस में होता रहा है। केंद्रीय बजट दस्तावेजों की कई सौ प्रतियां छापने की प्रक्रिया इतनी संवेदनशील और जटिल होती है कि इसकी छपाई से जुड़े हुए कर्मचारियों एवं मंत्रालय के अधिकारियों को प्रेस के भीतर ही दो हफ्ते तक रखा जाता है। इसके साथ ही इस दौरान इस कार्य में शामिल अधिकारियों की पहुंच सख्त तौर पर प्रतिबंधित रहती है।

बजट दस्तावेजों की छपाई शुरू होने के साथ ही पारंपरिक 'हलवा' समारोह आयोजित किया जाएगा, जो छपाई प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक होता है। यह समारोह अगले सप्ताह होने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2026–27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये उनका लगातार नौवां बजट होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020–21 में बजट को पहली बार कागज–रहित किया था। उस साल उन्होंने केंद्रीय बजट टैबलेट पर पढ़ा और सभी बजट दस्तावेज सांसदों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित किए गए थे। साथ ही 'यूनियन बजट मोबाइल ऐप' भी पेश किया गया था, ताकि आम जनता और सांसदों को बजट दस्तावेजों तक आसान डिजिटल पहुंच मिल सके। इस मोबाइल ऐप में कुल 14 बजट दस्तावेज शामिल हैं, जिनमें सालाना वित्तीय विवरण, अनुदान मांग, वित्त विधेयक और अन्य संबंधित दस्तावेज हैं।

उल्लेखनीय है कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का पहला मौका था जब केंद्रीय बजट की प्रतियां बड़े पैमाने पर प्रकाशित नहीं की गई थीं। आजादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को पेश किया गया था।

भारतीय खेल प्राधिकरण ने 26 खेलों में 323 असिस्टेंट कोच पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए

नई दिल्ली, 18 जनवरी। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने 26 खेल विधाओं में 323 असिस्टेंट कोच पदों पर भर्ती के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेल प्राधिकरण, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत है।

चयनित असिस्टेंट कोचों की तैनाती देशभर में स्थित साई के क्षेत्रीय केंद्रों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों या प्रशिक्षण केंद्रों में की जाएगी। इन पदों के लिए वेतनमान लेवल–6 के तहत 35,400 से 1,12,400 तक होगा (पूर्व में पे बैंड–II 9,300–34,800 + ग्रेड पे 4,200)।

इन खेलों में होगी भर्ती– असिस्टेंट कोच पदों के लिए जिन खेलों में रिक्तियां निकाली गई हैं, उनमें एथलेटिक्स (28), तीरंदाजी (12), बैडमिंटन (16), बास्केटबॉल (12), बॉक्सिंग (19), कैनोइंग (7), साइक्लिंग (12), फेंसिंग (11), हॉकी (13), फुटबॉल (12), जिम्नास्टिक्स (12), हैंडबॉल (6), जूडो (6), कबड्डी (6), खो–खो (2), रोइंग (11), सेपक टकरॉ (3), शूटिंग (28), स्विमिंग (26), टेबल टेनिस (14), ताइक्वांडो (11), टेनिस (8), वॉलीबॉल (10), वेटलिफ्टिंग (10), कुश्ती (22) और वुशु (6) शामिल हैं।

भर्तियां भारत सरकार की मानक आरक्षण नीति के अनुसार की जाएंगी। इसके अलावा प्रत्येक खेल विधा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

आवश्यक योग्यता में साई एनएसएनआईएस, पटियाला या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से कोचिंग में डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाणपत्र शामिल है। इसके अलावा ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल या विश्व चैंपियनशिप में भागीदारी के साथ कोचिंग का सर्टिफिकेट, अथवा संबंधित खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त उम्मीदवार भी पात्र होंगे।

उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा— पहले कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा और उसके बाद कोचिंग एबिलिटी टेस्ट।

असिस्टेंट कोच पद कोच कैडर में ग्रुप 'बी' का एंट्री लेवल पद है। चयनित कोच भविष्य में ग्रुप 'ए' के तहत कोच, सीनियर कोच, चीफ कोच और आगे चलकर हाई परफॉर्मेंस कोच के पद तक पदोन्नति के पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों की तैनाती देश में कहीं भी की जा सकती है और उनकी वरिष्ठता अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारित होगी।

भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी भारतीय खेल प्राधिकरण के आधिकारिक माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

इतिहास के पन्नों में 19 जनवरी : जब इंदिरा गांधी बनीं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 18 जनवरी। भारत के राजनीतिक इतिहास में 19 जनवरी का दिन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन वर्ष 1966 में इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। यह जिम्मेदारी उन्हें ऐसे समय में सौंपी गई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन से देश शोक में था।

कांग्रेस नेतृत्व ने शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी पर भरोसा जताया। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ, जब किसी प्रधानमंत्री की संतान ने उसी पद को संभाला, जिस पर पहले उनके पिता और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आसीन रहे थे।

इंदिरा गांधी का कार्यकाल भारतीय राजनीति के सबसे निर्णायक दौरों में गिना जाता है। वह 1967 से 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं और इसके बाद 1980 में दोबारा सत्ता में लौटीं। 31 अक्टूबर 1984 को उनके निधन तक उन्होंने देश का नेतृत्व किया।

दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत नेतृत्व के लिए पहचानी जाने वाली इंदिरा गांधी ने कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1971 का भारत–पाक युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण उनके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियां रहीं। वहीं 1975 में लगाए गए आपातकाल ने उन्हें आलोचनाओं के केंद्र में भी रखा।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र– 1649 – इंग्लैंड नरेश 'चार्ल्स प्रथम' के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ।
1839 – ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यमन के शहर अदन को जीत लिया।
1905 – बंगला साहित्यकार देवेन्द्रनाथ टैगोर ने आखरी सांस ली।
1927 – ब्रिटेन ने अपनी सेना को चीन भेजने का निर्णय लिया।
1942 – 'द्वितीय विश्वयुद्ध' के दौरान जापान ने बर्मा (वर्तमान म्यांमार) पर कब्ज़ा किया।
1960 – अमेरिका और जापान के बीच आपसी सुरक्षा समझौता हुआ।
1977 – समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध अमेरिका के मिआमी शहर में पहली बार बर्फ़ गिरी।
1986 – पहला कम्प्यूटर वायरस 'सी.ब्रेन' सक्रिय किया गया।

तनाव, चिंता और अनिद्रा से राहत देता है गोमुखासन, जान लें इसे करने का सही तरीका

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर। बदलता मौसम और व्यस्त दिनचर्या कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं की वजह बन सकते हैं। हालांकि, योगासन को दिनचर्या में शामिल कर मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है। ऐसे ही एक योगासन का नाम गोमुखासन है।

मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, गोमुखासन को बेहद फायदेमंद योगासन बताते हुए करने की सही विधि भी बताता है। इसका नियमित अभ्यास कंधों, छाती, रीढ़ की हड्डी और पैरों को लचीला बनाता है और तनाव के साथ थकान को भी दूर करता है।

एक्सपर्ट के अनुसार, गोमुखासन के नियमित अभ्यास से कंधों और पीठ के ऊपरी हिस्से में जकड़न दूर होती है। फेफड़े पूरी तरह खुलते हैं। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए विशेष लाभकारी है क्योंकि यह अग्न्याशय को उत्तेजित करता है। साथ ही तनाव, चिंता और अनिद्रा में भी राहत मिलती है।

गोमुखासन करने की विधि बहुत सरल है। सबसे पहले फर्श पर सीधे बैठ जाएं और दोनों पैर आगे की ओर फैला कर दंडासन मुद्रा में बैठें। रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी रखें। अब बायां पैर मोड़ें और उसकी एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रख दें। फिर दाहिना पैर मोड़कर उसकी एड़ी बाएं कूल्हे के पास रखें, इस तरह दाहिना घुटना बाएं घुटने के ठीक ऊपर आएगा। अब दाहिना हाथ कंधे के ऊपर से पीठ के पीछे ले जाएं और बायां हाथ कमर के नीचे से पीठ के

पीछे ले जाकर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाएं। जितना आराम से हो सके, हाथों को एक–दूसरे की ओर खींचें। नजरें सामने रखें, रीढ़ सीधी रखें और सामान्य गहरी सांस लें। इस स्थिति में 20–25 सेकंड तक रुकें। रोजाना कुछ मिनट करने से कंधे, छाती और कमर में लचीलापन आता है।

गोमुखासन का अभ्यास महिलाओं के लिए भी बेहद फायदेमंद है। पीरियड्स में होने वाली समस्याओं में यह आसन राहत देता है। गोमुखासन एक सरल आसन है, जिसके अभ्यास से कई लाभ मिलते हैं, हालांकि योग एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि शुरुआत में अगर हाथ पीठ पर नहीं मिल पाते तो रुमाल या पट्टी की मदद ली जा सकती है। कंधे या घुटने की गंभीर चोट वाले लोगों को डॉक्टर या योग प्रशिक्षक की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

पीएफ निकासी से पेंशन पेमेंट सिस्टम तक हुए कई बदलाव, हर कर्मचारियों को जानने चाहिए ये नियम

नई दिल्ली, 18 जनवरी।

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बीते साल 2025 बहुत खास रहा, क्योंकि इस दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ से जुड़े कई अहम बदलाव किए हैं। ये ऐसे बदलाव हैं, जो लगभग सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर डालते हैं। चाहे आप अपनी नौकरी बदल रहे हों, पीएफ निकालने की तैयारी कर रहे हों या नए कर्मचारी हों, आपके लिए इन बदलावों को समझना बेहद जरूरी है।

ईपीएफ योजना में कई प्रावधान होने के कारण पहले पीएफ निकासी प्रक्रिया जटिल थी, ईपीएफ निकासी प्रावधानों को 13 पैराग्राफ से एक पैराग्राफ में सरल बनाया गया है, जिसमें सरल पात्रता शर्तें शामिल हैं, सदस्य अब 75 फीसदी तक पीएफ आसानी से निकाल सकते हैं, जबकि शेष 25 फीसदी सेवानिवृत्ति बचत के लिए खाते में रखना होगा। अब पहले की 13 कैटेगरी को अब तीन में मिला दिया गया है, जिसमें जरूरी जरूरतें (बीमारी, पढ़ाई, शादी), घर से जुड़ी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं, जबकि अब आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि सिर्फ 12 महीने है।

मैनुअल क्लेम प्रोसेसिंग के कारण क्लेम सेटलमेंट में देरी होती थी, जिसमें सुधार किया गया है। पहले ऑटो एडवांस क्लेम सुविधा, जो पहले बीमारी के लिए थी, उसे घर, शादी और पढ़ाई तक बढ़ाया गया। इसकी लिमिट को 2025 में 5 लाख रुपया किया गया है, जबकि 47.48 फीसदी कुल क्लेम और 72.09 फीसदी एडवांस क्लेम ऑटो मोड में सेटल होते हैं। नौकरी बदलने के समय पीएफ ट्रांसफर के

लिए सदस्यों को मैन्युअल रूप से दावा दायर करना होगा जनवरी 2025 से ऑटो ट्रांसफर रिक्वेस्ट सुविधा शुरू हुई, जिसमें सदस्य और नियोक्ता की कोई भागीदारी नहीं थी दिसंबर 2025 तक 65.75 लाख मामले संसाधित हुए, जिससे पीएफ ट्रांसफर निर्बाध हो गया।

इससे पहले बैंक खाता सीडिंग के लिए नियोक्ता अनुमोदन आवश्यक होने से देरी होता था। अप्रैल 2025 से नियोक्ता अनुमोदन के बिना बैंक खाता सत्यापन की सुविधा शुरू हुई, 1.07 करोड़ मामले संसाधित हुए। चेक लीफ या पासबुक अपलोड करने में त्रुटियों के कारण होने वाली देरी के कारण एनपीसीआई और सूचीबद्ध बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन बैंक सत्यापन शुरू हुआ, बिना चेक अपलोड के दिसंबर तक 4.60 करोड़ दावे संसाधित हुए। पीएफ पासबुक केवल अलग पोर्टल पर उपलब्ध था, सदस्य पोर्टल पर पासबुक लाइट की शुरुआत हुई, जिससे अलग पोर्टल पर लॉगिन की जरूरत नहीं रही।

डाक से भेजे जाने वाले माल पर निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं लागू: सीबीआईसी

नई दिल्ली, 18 जनवरी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने भारत के ई–कॉमर्स सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए बड़ा पॉलिसी बदलाव किया है। सीबीआईसी ने कहा कि आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल जैसी निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं अब डाक के जरिए भेजे जाने वाले माल पर भी लागू होंगी।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि इसके तहत पोस्टल रूट से भेजे जाने वाले सामानों पर भी जरूरी निर्यात प्रोत्साहन दिए जाएंगे। 15 जनवरी, 2026 से लागू हुआ यह कदम छोटे एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क में शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन प्रोत्साहनों से सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों विशेष रूप से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों के निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है और डाक निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रालय ने कहा, ''सीबीआईसी ने 'ड्यूटी ड्रॉबैक', निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) और राज्य एवं केंद्रीय करों तथा शुल्क की छूट (आरओएससीटीएल) योजनाओं के तहत निर्यात से संबंधित लाभों को 15 जनवरी से डाक के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए गए निर्यातों तक विस्तारित कर दिया है।'' 'ड्यूटी ड्रॉबैक' निर्यात को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इसके तहत निर्यात किए गए माल के निर्माण या उत्पादन में उपयोग किए गए कच्चे माल पर चुकाए गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क (या उनके समकक्ष कर) का पूरा या आंशिक 'रिफंड' निर्यातक को दिया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस उपाय का उद्देश्य डाक माध्यमों का उपयोग करने वाले निर्यातकों के लिए समान अवसर प्रदान करना एवं सीमा पार ई–कॉमर्स के विकास के लिए एक अनुकूल तथा समावेशी परिवेश बनाना है।

सीबीआईसी ने इन लाभों को क्रियान्वित करने के लिए डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे निर्यातकों को डाक मार्ग से निर्यात किए गए माल के लिए 'ड्यूटी ड्रॉबैक', आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल लाभों का दावा करने में सक्षम बनाया जा सके। भारत में वर्तमान में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा–7 के तहत अधिसूचित 28 विदेशी डाकघर (एफपीओ) हैं।

सीबीआईसी ने डाक और 'कूरियर' माध्यमों से सीमा पार व्यापार को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा एवं प्रसंस्करण) विनियम, 2022 डाक निर्यात के लिए निर्यात घोषणाओं के संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण को सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा डाक आयात विनियम, 2025 को डाक आयात की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था। डाक निर्यात के लिए आईजीएसटी 'रिफंड' का स्वचालन सितंबर 2024 में लागू किया गया था।

विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड में

नई दिल्ली, 18 जनवरी।

विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन कल से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरु होगा। इसमें 3 हजार से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। पांच दिन के इस सम्मेलन में 100 से अधिक भारतीय सीईओ और सरकारी प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इसमें अश्विनी वैष्णव, प्रल्हाद जोशी और के राममोहन नायडू सहित वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री निवेशकों के लिए अपने–अपने राज्यों में व्यवसाय की संभावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्य सरकारों के पवेलियन भी वहां मौजूद हैं।

गणतंत्र दिवस 2026: इस बार वंदे मातरम' के 150 वर्ष को समर्पित भव्य राष्ट्रीय उत्सव

नई दिल्ली, 18 जनवरी।

गणतंत्र दिवस 2026 'वंदे मातरम' के गौरवशाली 150 वर्षों को समर्पित रहेगा। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' की स्पष्ट व प्रभावी छाप दिखाई देगी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 'स्वतंत्रता का मंत्र–वंदे मातरम' और 'समृद्धि का मंत्र –आत्मनिर्भर भारत' थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। परेड में कुल 18 मार्चिंग टुकड़ियां और 13 बैंड शामिल हैं।

वहीं, परेड के तुरंत बाद वायुसेना के फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई–30, पी–8आई, सी–130, सी–295, मिग–29, अपाचे, एलसीएच, एएलएच, एमआई–17 जैसे विमान व हेलीकॉप्टर शामिल रहेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं के स्वदेशी उपकरण एवं हथियार भी प्रदर्शित किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि होंगे।

वहीं 'वंदे मातरम' थीम पर विशेष आयोजन किए जाएंगे। 26 जनवरी की परेड में 6 राज्यों/व विभागों की झांकियां 'वंदे मातरम' विषय पर आधारित होंगी। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर जानकारी रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने दी। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की शुरुआत 100 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा पारंपरिक युद्ध–संगीत के साथ की जाएगी। भारतीय सेना का फेज्ड बैटल ऐरे फॉर्मेशन देखने को मिलेगा।

थल, जल और वायु सेनाओं की संयुक्त शक्ति का प्रदर्शन एक बड़ा आकर्षण होगा। सेना का भैरव दल, लद्दाख स्काउट्स, ड्रोन शक्ति, शक्तिबान और पशु दल (जांस्कर पोनी, बैक्ट्रियन ऊंट, श्वान) भी परेड का हिस्सा हैं। 26 जनवरी परेड के बाद होने वाली बीटिंग रिट्रीट समारोह में सभी बैंड 'वंदे मातरम' की धुन बजाएंगे। कर्तव्य पथ पर

बड़ी स्क्रीन पर 'वंदे मातरम' से जुड़े वीडियो प्रदर्शित किए जाएंगे। गुब्बारों के माध्यम से भी 'वंदे मातरम' बैनर का विमोचन किया जाएगा।

यही नहीं, 19 से 26 जनवरी तक देश भर के 126 शहरों में 234 स्थानों पर पैन इंडिया बैंड परफॉर्मेंस दी जाएगी। 26 जनवरी के आमंत्रण पत्र, टिकट और पुष्प सज्जा भी इसी थीम पर आधारित हैं। नागरिकों की सुविधा की बात करें तो दिल्ली मेट्रो 26 जनवरी को सुबह 3 बजे से शुरू होगी। गणतंत्र दिवस के निमंत्रण व टिकट धारकों के लिए मेट्रो यात्रा निशुल्क रहेगी। 26 जनवरी परेड स्थल पर सभी एनक्लोजर्स में दिव्यांग–अनुकूल रैम्प की व्यवस्था की जाएगी।

एनसीसी और माय भारत के स्वयंसेवक मार्गदर्शन के लिए तैनात रहेंगे। परेड देखने आने वाले लोगों के लिए क्लॉक रूम, पेयजल, शौचालय व प्राथमिक चिकित्सा आदि की व्यवस्था की जाएगी। एनक्लोजर्स के नाम नदियों और बीटिंग रिट्रीट के लिए वाद्य यंत्रों पर रखे गए। ट्रैफिक, पार्किंग और बैठने की जानकारी राष्ट्रपर्व पोर्टल और ऐप पर उपलब्ध होगी।

जोखिम भरे अभियानों में भारतीय सेना को मिलेगा फायर फाइटिंग रोबोट का साथ

नई दिल्ली, 18 जनवरी।

भारतीय सेना लगातार आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपना रही है। अब इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। सेना अग्निशमन के कार्यों में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी और रोबोट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सेना द्वारा खरीदे जाने वाले ये रोबोट फायर फाइटिंग रोबोट कहलाते हैं और ये अग्निशमन के कार्य में माहिर हैं।

दरअसल, यह फायर फाइटिंग रोबोट एक कॉम्पैक्ट, बहुउपयोगी और मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। इसे अत्यधिक जोखिमपूर्ण और खतरनाक अग्निशमन परिस्थितियों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। यह ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक काम करता है, जहां मानव हस्तक्षेप जोखिमपूर्ण होता है। यह रोबोट सुरक्षित दूरी से अग्निशमन कार्यों को अंजाम देने में सक्षम है। इससे आपातकालीन और संकटपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय सेना के अग्निशमन कर्मियों की सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भारतीय सेना ने इनोवेशन फॉर डिफेन्स एक्सीलेंस (आईडेक्स) के अंतर्गत फायर फाइटिंग रोबोट की महत्वपूर्ण खरीद संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सेना का कहना है कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारतीय सेना के मुताबिक फायर फाइटिंग रोबोट की खरीद के लिए यह अनुबंध स्वदेशी कंपनी एम्प्रेसा प्राइवेट लिमिटेड के

साथ किया गया है।

यह फायर फाइटिंग रोबोट मूल रूप से इनोवेशन फॉर डिफेन्स एक्सीलेंस ढांचे के अंतर्गत भारतीय बलों के लिए विकसित किया गया था। सक्षम प्रावधानों का उपयोग करते हुए, भारतीय सेना ने इसे पहली बार अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाने का फैसला किया है। यह खरीद सिंगल स्टेज कॉम्पोजिट ट्रायल के आधार पर की गई है। यह प्रक्रिया रक्षा सेवाओं के बीच आपसी सहयोग, संयुक्तता और तकनीकी एकीकरण को सशक्त बनाती है। सेना का मानना है कि यह पहल रक्षा स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती प्रदान करती है। डिफेन्स इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन के अंतर्गत संचालित इनोवेशन फॉर डिफेन्स एक्सीलेंस, सशस्त्र बलों और स्टार्ट–अप्स व नवोन्मेषकों के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। रक्षा स्टार्ट–अप समुदाय में इसे व्यापक स्वीकृति मिली है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन पर 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली, 18 जनवरी।

भारत के विमानन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन इंडिगो पर दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर हुई उड़ान विघटन की घटनाओं के लिए 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को दी।

नियामक के अनुसार, इंडिगो ने 3 से 5 दिसंबर के बीच 2,507 उड़ानें रद्द कीं और 1,852 उड़ानों में देरी हुई, जिससे देश भर के हवाई अड्डों पर तीन लाख से अधिक यात्री फंस गए। यह अव्यवस्था व्यापक असुविधा पैदा करने के साथ ही एयरलाइन की संचालन क्षमता और तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

डीजीसीए द्वारा लगाए गए कुल जुर्माने में 1.80 करोड़ रुपए का एकमुश्त दंड शामिल है, जो नागरिक उड्डयन नियमों के कई उल्लंघनों के लिए है। इसके अलावा, डीजीसीए ने 68 दिनों तक संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों का पालन नहीं करने के लिए रोजाना 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इससे 20.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दंड जुड़ गया, और कुल जुर्माना 22.20 करोड़ रुपए हो गया।

इंडिगो ने प्रतिक्रिया में कहा कि वह डीजीसीए के आदेशों का पूरी तरह पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और समय पर उचित कदम उठाएगी। डीजीसीए ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसने पाया कि इस संकट का कारण ऑपरेशंस का अत्यधिक अनुकूलन, नियामक तैयारियों की कमी, योजना सॉफ्टवेयर में कमजोरियां और प्रबंधन एवं संचालन नियंत्रण में अंतराल थे।

जांच समिति ने यह भी देखा कि इंडिगो का प्रबंधन योजना में कमियों की पहचान नहीं कर सका, पर्याप्त संचालन बफर नहीं रखा, और संशोधित एफडीटीएल नियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया। इन विफलताओं के कारण उच्च यात्रा अवधि में उड़ानों में बड़े पैमाने पर देरी और रद्दीकरण हुआ।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि एयरलाइन ने अधिकतम विमान और चालक दल के उपयोग के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई। इससे विघटन के समय रिकवरी के लिए बहुत कम अवसर बचा और चालक दल पर अतिरिक्त काम, डेड–हेडिंग और टेल स्वैप का दबाव पड़ा, जिससे संचालन क्षमता कमजोर हुई।

गमले में कैसे लगाएं फ्रेंच मैरीगोल्ड? इस तरह बालकनी–छत पर खिलेंगे रंग–बिरंगे फूल

नई दिल्ली, 18 जनवरी।

फ्रेंच मैरीगोल्डएक ऐसा फूलदार पौधा है, जिसे कम जगह और कम देखभाल में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसके छोटे, घने और रंग–बिरंगे फूल बालकनी, छत और घर की शोभा को काफी बढ़ा देते हैं। आप इसे सर्दी में भी आसानी से गमले में लगा सकते हैं। फ्रेंच मैरीगोल्ड के पौधे को लगाने के कुछ खास टिप्स हम लेकर आए हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं।

फ्रेंच मैरीगोल्ड का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले सही गमले का चयन करना बहुत जरूरी है। आप इसके लिए 6 से 8 इंच गहरा और चौड़ा गमला ले सकते हैं। वहीं, गमले के नीचे पानी निकास के लिए छेद जरूर करें। गमले में पानी के जलभराव के कारण पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं।

अब पौधे के लिए मिट्टी तैयार करें। इस पौधे के लिए हल्की और गार्डन वाली मिट्टी सबसे बेहतर होती है। आप बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट के साथ थोड़ी–सी रेत भी मिला सकते हैं। इससे मिट्टी पोषक तत्वों

से भरपूर हो जाती है और जड़ें आसानी से फैलती हैं।

मिट्टी तैयार होने के बाद फ्रेंच मैरीगोल्ड का पौधा किसी पास की नर्सरी से खरीदकर लगा सकते हैं। पौधे को मिट्टी में लगाने के बाद ऊपर से हल्का पानी डालें।

फ्रेंच मैरीगोल्ड को भरपूर धूप पसंद होती है। इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें, जहां रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप मिले। बालकनी या छत इसके लिए सबसे सही जगह होती है। धूप मिलने से पौधा तेजी से बढ़ता है और ज्यादा फूल देता है।

भारत में नदी पाई जाने वाली डॉल्फ़िन के व्यापक क्षेत्र के आकलन का दूसरा अभियान शुरू

नई दिल्ली, 18 जनवरी।

पिछले वर्ष मार्च में गुजरात के गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पहले दौर के गणना अनुमान के परिणाम जारी किए जाने के बाद अब देश में डॉल्फ़िन के संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन के तहत नदी एवं मुहाना क्षेत्र में पाई जाने वाली डॉल्फ़िन का दूसरा व्यापक अनुमान शुरू किया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने पिछले वन्यजीव सप्ताह के दौरान देहरादून में डॉल्फ़िन की अखिल भारतीय गणना और उसके गणना प्रोटोकॉल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम का समन्वय भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून द्वारा राज्य वन विभागों और सहयोगी संरक्षण संगठनों डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, आरण्यक और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के वन कर्मचारियों के लिए कल बिजनौर में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें सर्वेक्षण की प्रगति के साथ–साथ मानकी–कृत क्षेत्रीय क्षमता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 10–15 जिलों के लिए समय–समय पर आगे प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

सर्वेक्षण की शुरुआत तीन नावों में सवार 26 शोधकर्ताओं के साथ हुई जिन्होंने पारिस्थितिक और पर्यावास संबंधी मापदंडों को रिकॉर्ड किया और जलमग्न ध्वनिक निगरानी के लिए हाइड्रोफोन जैसी तकनीकों का उपयोग किया। पहले चरण में सर्वेक्षण बिजनौर से गंगा सागर तक गंगा के मुख्य भाग और सिंधु नदी क्षेत्र में किया जाएगा। दूसरे चरण में यह ब्रह्मपुत्र, गंगा की सहायक नदियों, सुंदरबन और ओडिशा को समाहित करेगा।

दुनिया के अनोखे देश: जहां खुद जनता ही चलाती है शासन

नई दिल्ली, 18 जनवरी।

दुनिया भर में ज्यादातर देशों की पहचान उनकी सरकार, संविधान और सेना से होती है. परंतु कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां न तो कोई स्थायी सरकार है और न ही कोई सेना. ये देश अपने अलग तरीकों से शांति और व्यवस्था बनाए रखते हैं.

सैन मारिनो यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है. यह दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है. यहां कोई स्थायी सेना नहीं है, केवल एक प्रतीकात्मक गार्ड होता है. इस देश की सरकार हर छह महीने में बदल जाती है और दो 'कैप्टन रीजेंट्स' मिलकर शासन चलाते हैं. सैन मारिनो का मानना है कि शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व से ही स्थिरता बनी रहती है.

आइसलैंड यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है, जिसके पास अपनी कोई सेना नहीं है. यहां की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और कोस्ट गार्ड निभाते हैं. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आइसलैंड ने सैन्य बजट पर बिल्कुल भी खर्च नहीं किया है और यह आज भी दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है.

लाइबेरलैंड डेन्यूब नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा

इलाका है, जो क्रोएशिया और सर्बिया के बीच बसा है. 2015 में इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, हालांकि इसे अभी तक कोई आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है. यहां न कोई सरकार है और न ही कोई सेना. इसकी विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यूनतम शासन पर आधारित है.

वेटिकन सिटी कैथोलिक चर्च का केंद्र है और यह दुनिया का सबसे छोटा देश भी है. यहां पोप शासन करते हैं, और यह देश पूरी तरह धार्मिक प्रशासन के अंतर्गत आता है. इसकी कोई सेना नहीं है, बल्कि स्विस गार्ड नामक एक छोटी सी सुरक्षा टुकड़ी पोप की रक्षा करती है.